मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 48 | जून 1992 | 50 पैसे

सट्टा बाजार

सरकारी आमदनी का एक और जरिया

हर्ष और विषाद का सट्टा बाजार से चोली-दामन का साथ है। २ अप्रैल को स्टेट बैंक आफ इंडिया में ६२२ करोड़ रूपये की हेरा-फेरी ने पाँच हजार करोड़ रूपयो के घोटाले की झलक दिखाई है। हर्ष ने विषाद कुछ अधिक ही गहरा कर दिया—सदमे में एक बैंक के अध्यक्ष की मौत हो गई है। "पूरे बैंकिंग व्यवसाय को लोग शक-ओ-शुबह की नजर से देखने लगे हैं" भारत सरकार की नई नीतियों की आड़ में सट्टा बाजार में शेयरों के उछलते भावों पर २ अप्रैल को ब्रेक लगा और तबसे पहिया उल्टा घूम रहा है। "सट्टा बाजार को किसी की नजर लग गई है!" नजर-वजर से बचने के लिये अन्धविश्वासी काला टीका-गन्डा ताबीज का सहारा लेते हैं और यही यहाँ के हुक्मरान कर रहे हैं। आइऐ मामले को थोड़ा कुरेद कर देखें।

फर्जी पूंजी, काल्पनिक पूंजी का उदय सट्टा बाजार के जन्म के साथ का है। टैक्सों से जुड़े असन्तोष को टालने के वास्ते पाँच-दस-बीस साल वाले बान्ड-सैक्युरिटी जारी करके अपने खर्च चलाने के लिये धन एकत्र करना पूंजीवादी सरकारों के लिये सामान्य बात है। फिक्स इनकम वाले ऐसे बान्ड भरे पेट वालों के लिये न्यूनतम रिस्क वाले सौदे रहे हैं—युद्ध-बगावत की स्थिति में किसी सरकार का दिवाला पिटने पर उसके बान्ड आदि बेशक रद्दी कागज साबित होते है। सरकारों द्वारा बान्ड आदि के जरिये इक्ठ्ठा किया गया धन आमतौर पर सरकारी तन्त्र पर खर्च हो जाता है पर उस पर ब्याज बरसों बाद तक दिया जाता है व वापसी के समय मूलधन लौटाया जाता हैं। जो खर्च किया जा चुका है, खाया जा चुका है उसके इस प्रकार के व्यवहार की वजह से ही पूंजी के मार्क्सवादी विश्लेषण में उसे फर्जी पूंजी कहा जाता हैं। खैर।

पुलिस - फौज-मन्त्री- मन्तरी-अफसर वाले तन्त्र के लगातार बढ़ते जाने ने सरकारों के खर्च बढ़ाने के साथ दुनिया भर में फर्जी पूंजी की मात्रा बहुत बढ़ा दी है। आज विश्व की रूपया-पैसा मंडियों में शेयरों से कई गुणा अधिक खरीद-फरोख्त सरकारों के बान्डों की होती है। भारत में ही केन्द्र सरकार-राज्य सरकारों-सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी बान्डों आदि का कारोबार एक लाख करोड़ रूपये सालाना का हो गया है। जिक्र कर दें, टालने की यह सरकारी नीति सिर पर चढ कर बोलती है—केन्द्र सरकार के उद्योगों की २९ प्रतिशत हिस्सेदारी बेच कर प्राप्त धन के एक भाग द्वारा भारत सरकार अपने बान्डों पर इस साल की १,१५० करोड़ रूपये से अधिक की देनदारी का भुगतान करेगी।

बढती देनदारी की समस्या से पार पाने के लिये सरकारें दमन-शोषण तो बढा ही रही हैं, हेरा-फेरियों के जरिये धन एकत्र करने की स्कीमें भी सामान्य सरकारी नीतियाँ बन गई हैं। सोने के सिक्कों में खोट, मिलावट के जरिये धन एकत्र करने जैसी बीते जमाने की तिकड़में आज की हेरा-फेरियों के सामने बच्चों के खेल हैं। इस सिलसिले में आइये आज के सट्टा बाजार पर एक नजर डालें।

शराब-सिगरेट-लाटरी की ही तरह सट्टा बाजार भी सरकारों की आमदनी का एक जरिया है। सट्टा बाजार आजकल सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र में भारत में हाल के घोटाले को देखें।

यूनिट ट्रस्ट-बीमा-बैंक भारत में केन्द्र सरकार के हैं। अपनी खस्ता होती हालत के सुधारने के लिये कुछ समय पहले इन्होंने सट्टा बाजार में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया और चाँदी कूटने लगे। सट्टा बाजार में सक्रियता बढी। फर्जी पूंजी तक को 'उत्पादक' बनाने के स्वर्ण अवसर दलालों और सरकारी साहबों ने पैदा किये—शायद पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र में यह अनूठा भारतीय योगदान है। सरकार की नई आर्थिक नीतियों की आड़ में शेयरों के भावों को फर्जी पूंजी के इस्तेमाल के जरिये नित नई ऊँचाइयों की ओर धकेला गया- उद्योगों के उत्पादन से शेयरों के इन भावों का कोई सम्बन्ध नहीं था। छुट-पुट बचत करने वाले लाखों लोगों को इन हालात में सट्टा बाजार की ओर आकर्षित होना ही था—पाई-पाई जोड़ने की बजाय गड्डियाँ उनकी आखों के आगे नाच रही थी। एक हद तक फुलाने के बाद बुलबुले को फोड़ना/उसका फूटना लाजमी था—अन्यथा मुनाफा कहाँ से आता। २ अप्रैल को गुब्बारे में सूई चुभाई गई और अपनी बचत से सट्टा खेलने आये लाखों लोगों के करोड़ों रूपये गायब हो गये- सरकार और बिचौलियों की तिजोरियों में पहुँच गये। इतने बड़े आपरेशन में किसी का फेर में पड़ कर जान गँवाना अथवा किसी हर्ष का विषाद के समुद्र में गोते लगाना तो साइड इफैक्ट हैं। रस्मी शोर, सरकार द्वारा जाँच तथा कार्रवाई आदि जरूरी थे ताकि अपनी बचत से सट्टा खेलने वालों को पुचकारा जा सके और अगले राउन्ड के लिये उन्हें तैयार किया जा सके।

शेयरों में आने वाली लाजमी तेजी की चर्चा बड़े अखबारों में शुरू भी हो गई है; यूनिट ट्रस्ट और अन्य सरकारी म्यूचुअल फन्डों के पास शेयरों में लगाने के लिये रूपयों का अम्बार लग गया है—मास्टर गेन, मास्टर प्लान, बैंक आफ इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्दु-प्रकाश, जो आई सी ग्रोथ स्कीम प्राइवेट म्यूचुअल फंड, भी बहुत जल्दी सट्टा बाजार में आने वाले हैं विदेशी निवेशक भी शीघ्र ही यहाँ के सट्टा बाजार में प्रवेश करेंगे... निकट भविष्य में शेयरों में आने वाली तेजी को कोई रोक नहीं सकता! पूंजीवादी डुगडुगी को बजती छोड़ आइये हम जड़ की कुछ चर्चा के साथ यह बात खत्म करें।

वास्तव में संकट सम्पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का है। उद्योगों में संकट इसका एक लक्षण है तो बैंकों में सँकट दूसरा लक्षण—अमरीका में बड़े बैंकों के दिवालिया होने की रफ्तार काफी बढ गई है और उद्योग महाबली जनरल मोटर को १९९१ में करोड़ या अरब में नहीं बल्कि खरब रूपयों का घाटा हुआ है; ६४ खरब ५० अरब रूपयों के खराब कर्ज बट्टे-खाते में डालने की मजबूरी और उद्योग में छा रही मन्दी से जापानी बैंकों की हालत खस्ता हो रही है। और पूंजीवादी व्यवस्था का संकट गहरा रहा है। ऐसे में सट्टेबाजी और सट्टेबाजी में अधिक रिस्क लेना सामान्य घटना-क्रम है। फर्जी पूंजी का बड़ा होता पहाड़, पुलिस-फौज वाला फूलता राक्षस, बढता सामाजिक असन्तोष पूंजीवादी मार-काट अथवा विश्वव्यापी नई समाज रचना, दो में से एक को चुनना हमारे लिये जरूरी हो गया है।

हितकारी पोट्रीज

मजदूरों को झुकाने में कामयाब होने के बाद ११ जनवरी को की तालाबन्दी मैनेजमेन्ट ने १५ मई को उठाई। बरसों से काम कर रहे ६०० कैजुअल वरकरों को मैनेजमेन्ट ने निकाल दिया है। ४१ परमानेन्ट मजदूर डिसमिस और ५०-६० सस्पैन्ड कर दिये गये हैं। ११ जनवरी से पहले स्लो डाउन की जाँच के नाम पर मजदूरों पर मैनेजमेन्ट तलवार ताने रहेगी। मैनेजमेन्ट के पक्ष में हुआ ९१ वाला एग्रीमेन्ट लागू रहेगा। १५ सुपरवाइजरों और फैक्ट्री मैनेजर की भी छुट्टी कर दी गई है। मजदूरों को १००० रूपये एडवान्स दिये गये हैं जो कि २० किस्तों में कटेंगे।

आतंक और दहशत के माहौल में प्याली मजदूरों से अत्यधिक काम लिया जा रहा है—बरकर बहुत कम कर दिये जाने के बाद भी फस्ट प्लान्ट में पहले के लगभग प्रोडक्शन होने लगा है, II प्लान्ट में भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है। फैक्ट्री में काम कर रहे वरकरों को और डराने के लिये मैनेजमेन्ट ने निकाले हुये तीन मजदूरों को गुन्डों से पिटवाया है। तीन यूनियनों के बेसुरे राग जले पर नमक छिड़क कर माहौल को और खराब कर रहे हैं।

१९७८ के संघर्ष में लगी ठोकर के बाद इस संघर्ष में प्याली मजदूरों को फिर ठोकर लगी है। निराशा-हताशा के वर्तमान माहौल में भी हितकारी मजदूरों को यह समझने की जरूरत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों और मैनेजमेन्टों के बीच टकराव अनिवार्य हैं—किसी की छाया को इसका कारण मानना और उसे दूर करने के लिये हितकारी मैनेजमेन्ट द्वारा करवाई गई पूजा एक और उदाहरण मात्र है पूंजीवादी अन्धविश्वास का। अन्य फैक्ट्रियों की ही तरह आने वाले दिनों में प्याली में भी संघर्ष बढ़ेंगे। इसलिये इस बार लगी ठोकर की जाँच-परख जरूरी है ताकि गलतियाँ दोहराई नहीं जायें। मजदूर पक्ष के उभरने और उसके ताकतवर बनने के लिये घटनाक्रम का रिव्यू जरूरी है। इस अखबार के कई अंकों में हमने हितकारी पोट्रीज की घटनाओं की चर्चा की है, उन पर एक नजर डालना प्याली फैक्ट्री मजदूरों के लिये उपयोगी होगा। मजदूर पक्ष के निर्माण में हाथ बँटाने के इच्छुक हितकारी मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था का बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ का ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लियेबेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटाचौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद121001

आई आई टी कानपुर

इस प्रमुख शिक्षण संस्था में श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जारहा है, समझौतों को प्रशासन तोड़ रहा है। इस सब के विरोध में कर्मचारी संगठन द्वारा आवाज उठाने पर प्रशासन उसकी गतिविधि पर पाबन्दी का अदालत से आदेश ले आया। करोड़ों रूपयों की हेरा-फेरी पर सवाल उठाने पर कर्मचारी संगठन के प्रधान और महासचिव सस्पैन्ड तो कर ही दिये गये हैं, आई आई टी में उनके प्रवेश तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाईयों के खिलाफ कर्मचारी कदम उठा रहे हैं।

आशा है कि कानपुर की शिक्षण संस्थाओं के वरकरों तथा क्षेत्र के फैक्ट्री वरकरों के आन्दोलनों के बारे में आगे से कुछ विस्तार से हम चर्चा कर सकेंगे।

हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीज

आटो पार्टस बनाने वाली २४ सैक्टर की इस फैक्ट्री में ४५ परमानेन्ट और ३५ कैजुअल व ठेकेदारी वरकर काम करते थे। यूनियन लीडरों का विरोध करने पर दो मजदूरों को मैनेजमेन्ट ने १४ फरवरी को सस्पैन्ड कर दिया। मैनेजर से हाथा पाई के आरोप में २६ फरवरी को सस्पैन्ड वरकरों को गिरफ्तार करवा दिया गया। इस पर आवाज उठने पर लीडरों ने सब मजदूरों से साफ-साफ कह दिया कि वे मैनेजमेन्ट के साथ हैं, मजदूरों से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। यूनियन सीटू की है। १२ मार्च को मैनेजमेन्ट ने डाई कास्टिंग के सभी वरकरों (२३) और इन्सपैक्शन के ५ वरकरों का गेट रोक दिया। मजदूरों को सस्पैन्ड लैटर आदि कुछ नहीं दिया गया। १२ मार्च को ही वरकरों ने नये लीडर चुने।

टूल रूम में काम जारी रहा। इन्सपैक्शन और डाई कास्टिंग में नये कैजुअल वरकर भरती करके मैनेजमेंट काम करवा रही है। निकाले हुये मजदूरों को हड़ताल पर बता कर मैनेजमेंट अदालत से २०० गज वाला स्टे ले आई।

मजदूर बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने हड़ताल नहीं की है बल्कि मैनेजमेंट ने उनका गेट रोका है पर लेबर डिपार्टमेंट तारीख पर तारीख देकर मजदूरों से चक्कर कटवाती रही। तीन महीने यह करने के बाद डी एल सी ने मजदूरों से कहा कि मैनेजमेन्ट मानती नहीं इसलिये डिमान्ड नोटिस दो। मजदूरों ने डिमान्ड नोटिस भी दे दिया है और चार-पाँच साल की उठा-पटक के लिये तैयार हो रहे हैं। लेबर डिपार्टमेन्ट हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीज मैनेजमेन्ट के अनुचित श्रम व्यवहार तथा गैर-कानूनी कार्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ?

"हड़ताल" और हड़ताल

हड़ताल का मतलब है पूरी उत्पादन प्रक्रिया को ठप्प कर देना। जनरल स्ट्राइक का परिणाम पूंजीवादी व्यवस्था पर करोड़ों अरबों की चोट करना होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में काफी समय तक हड़ताल मजदूरों के हाथ में एक धारदार हथियार रही है। पूंजीपति और सरकारें हड़ताल से घबराते रहे हैं। हड़ताल न होने देने के लिये, हड़ताल तोड़ने के लिये गुण्डों से लेकर पुलिस-सेना तक का इस्तेमाल आम बात रही है। परन्तु अब हड़तालें तीन तरह की हो गई है। असली, रस्मी और फर्जी।

जब से मजदूर आन्दोलन में ट्रेड-यूनियन लीडरों की भूमिका मैनेजमेन्ट की पॉलिसी लागू करने वाले बिचौलियों में बदली है तब से ट्रेड-यूनियन वाली हड़तालें आम-तौर पर रस्मी अथवा फर्जी बन गई है। रस्मी हड़तालें मैनेजमेन्ट को बिचौलियों की ताकत दिखाने के लिये और फर्जी हड़तालें मजदूरों को फँसाने के लिये। कई बार रस्मी और फर्जी हड़ताल की खिचड़ी भी पकती है।

केन्द्रीय लीडरों द्वारा घोषित रस्मी हड़तालें आजकल फैक्ट्री स्तर पर फर्जी हड़ताल में बदल जाती है। आइये ऐसी हड़ताल का थोड़ा पोस्ट मार्टम करें। बड़े लीडरों की देश-व्यापी अथवा राज्य-व्यापी हड़तालों के दौरान उनके फैक्ट्री स्तर के लीडरों द्वारा मैनेजमेन्टों से बड़े पैमाने पर ऐसे समझौते किये जाते हैं। जिनके अनुसार हड़ताल या बन्द के दिन के बदले छुट्टी के दिन मजदूरों से काम लिया जाता है। ऐसी हड़तालों का मतलब 'अग्रिम' छुट्टी हो गया है। आज से सौ साल पहले पूंजीपतियों के एक सरगने ने जहाँ यह कहा था—'हड़ताल अपने में क्रान्ति का अजगर छुपाए होती है।" वही आज के लुटेरे हड़ताल के समय काल में तेल डालकर सोये रहते हैं। जाहिर है कि रस्मी और फर्जी हड़ताल की खिचड़ी मजदूर आन्दोलन के लिये घातक है। यह "हड़तालें" आन्दोलन को कुंठित करती हैं। और बिचौलियों को स्थापित करने का काम भी करती है। इन हालत में मजदूर पक्ष के उभरने के लिए रस्मी-फर्जी हड़तालों की हकीकत को उजागर करना तो जरूरी है ही, ऐसे मौकों को वास्तविक हड़ताल में बदलने की जो थोड़ी सी संभावना पैदा होती है उसे ध्यान में रखकर काम करना भी आवश्यक है।

वस्तुत नियन्त्रण के लाख कोशिशों के बावजूद रस्मी-फर्जी हड़तालें कभी-२ वास्तविक हड़ताल में बदल जाती है। उदाहरण के लिये जर्मनी में ट्रेड यूनियनों की हाल की हड़ताल जो कि यूनियन लीडरों और सरकार के प्रयासों के बावजूद एक वास्तविक हड़ताल में बदल गई। सफाई मजदूरों से शुरू होकर पूरी जर्मनी में फैली यह हड़ताल प्रभावशाली साबित हुई है। फरवरी १९८९ में कानपुर कपड़ा मिल मजदूरों का रेल रोको आन्दोलन भी वास्तविक हड़तालों के श्रेणी में आता हैं। मजदूरों को ट्रेड यूनियनों-पूंजीवादी पार्टियों के आम हड़ताल या बन्द के आह्वानों को रस्मी फर्जी के अखाड़े से बाहर खींचकर पूंजीवाद पर चोट करने के मौके के रूप में बदलने की कोशिश करनी चाहिये।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के १६ जून १९९२ में भारत व्यापी बन्द के दौरान उपरोक्त बातों पर गौर करें।

टेलीफोन इन्डस्ट्रीज

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, मनकापुर (जिला गोण्डा) भारत सरकार का कारखाना है। आई टी आई करने और फिर अप्रेन्टिस करने के पश्चात दो-तीन साल से लगातार काम कर रहे २०८ वरकरों को मैनेजमेंट ने २९ सितम्बर ९१ को बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्री से निकाल दिया। सरकारी कानून है कि २४० दिन लगातार काम करने के बाद मजदूर परमानेन्ट हो जाते हैं लेकिन यहाँ सरकारी कारखाने की मैनेजमेन्ट ने दो-तीन साल से लगातार काम कर रहे वरकरों को कैजुअल करार दे कर निकाल दिया है। मजदूरों को गुमराह करने के लिये आरम्भ में मैनेजमेंट ने इन्टरव्यू द्वारा रेगुलर करने का प्रलोभन दिया पर यह शुद्ध धोखा निकला। एस डी एम-डी सी-एम एल ए-एम पी-केन्द्रीय संचार मंत्री-मुख्यमन्त्री को ज्ञापन, फैक्ट्री गेट पर धरना-मनकापुर से लखनऊ पैदल यात्रा-आमरण अनशन जैसे कदम मजदूर उठा चुके हैं पर आश्वासनों के पहाड़ से अधिक कुछ भी उन्हें नहीं मिला है। आशा है कि मनकापुर में मजदूरों द्वारा इन हालात से निपटने के लिये उठाये कदमों के बारे में हम आगे विस्तार से जानकारी दे सकेंगे।

क्लच आटो

मैनेजमेन्ट द्वारा एग्रीमेन्ट अनुसार परमानेन्ट मजदूरों के १५० रूपये नहीं बढ़ाने पर आरम्भ हुई खींचा-तान में चार अप्रैल को २५० कैजुअल मजदूर नौकरी से निकाल दिये गये थे और २७ अप्रैल को १२ परमानेन्ट मजदूर सस्पैन्ड कर दिये गये थे। इसकी चर्चा हमने पिछले अंक में की थी इस बीच मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच खींचा-तान तीखी हुई और ११ मई से क्लच आटो में हड़ताल है।

क्लच आटो में भी घटनायें जगे-जगाये ढर्रे पर हो रही हैं। पुराने तरीकों के बार-बार नाकारा साबित होने और जगह-जगह मजदूरों को चोट पहुँचाने का जिक्र करते हुये हमने क्लच आटो मजदूरों को खतरों से आगाह किया था लेकिन यह मजदूर भी नेताओं के मुंह ही ताकते रहे हैं। इसके नुक्सान नजर भी आने लगे हैं...

मई के अन्त तक १०० कैजुअल मजदूरों को हिसाब लेने को मजबूर करके मैनेजमेन्ट ने २५० कैजुअल वरकरों को परमानेन्ट करने की डिमान्ड को अनदेखी बनाने की बुनियाद पक्की की। और क्लच आटो फैक्ट्री गेट पर ताश खेलते मजदूर हैं कि लीडरों की लेबर डिपार्टमेन्ट अफसरों आदि के पास भाग-दौड़ पर अब भी आस लगाये हैं।

मजदूरों की एक और असफलता का उदाहरण मात्र बनने से बेचने के लिये क्लच आटो मजदूरों को पिटी-पिटायी राह छोड़ कर आन्दोलन की नई राह पर बढ़ना होगा। फौरन कदम नहीं उठायेंगे तो छब्बे की बजाय यह मजदूर भी दूबे ही बनेंगे—थामसन प्रेस, हितकारी पोट्रीज, एवरी इंडिया की घटनाओं से सीखें। क्लच आटो मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

इलोफिक इन्डस्ट्रीज

आयल फिल्टर बनाने वालों में इलोफिक एक जानी-मानी कम्पनी है। इसने फरीदाबाद ओखला-नोयडा में छह सात छोटे-छोटे प्लान्ट बना रखे हैं। दिल्ली फरीदाबाद बोरडर स्थित I प्लान्ट में ११० परमानेन्ट और १५० कैजुअल वरकर काम करते हैं। १४/४ मथुरा रोड स्थित II प्लान्ट आठ साल से चल रहा है पर इसमें एक भी मजदूर परमानेन्ट नहीं है। इलोफिक II प्लान्ट के मजदूरों की ई एस आई कटती थी पर प्रोविडेन्ट फन्ड नहीं कटता था इन मजदूरों को हाजरी कार्ड नहीं दिया जाता था। यहां काम रहे ७०-८० मजदूरों ने संगठित होकर परमानेन्ट किये जाने की डिमान्ड की। इस पर मैनेजमेन्ट ने ३१ मार्च से ले आफ लगा दिया। ७ मई से ले आफ लगाना भी मैनेजमेन्ट ने बन्द कर दिया और मजदूरों को डियुटी पर भी नहीं लिया। उल्टे, मैनेजमेन्ट अदालत से १०० गज वाला स्टे ले आई। ऊपर से, ले आफ का पैसा मजदूरों को नहीं दिया गया है।

फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन्द है और मैनेजमेन्ट दबाव दे रही है कि मजदूर इस्तीफे दे कर हिसाब ले लें। इलोफिक मजदूर फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठे हैं और लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। इलोफिक मैनेजमेंट के अनुचित श्रम व्यवहार और गैर-कानूनी कार्य के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करती ? इलोफिक मजदूरों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिये हर रोज जलूस जैसे कदमों पर विचार करना चाहिये।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित